

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारी:—श्री बी०एल०मेहरड़ा, आर०ए०एस०)

अपील संख्या:—223 / 2017 / 223 (2017 / 00223)

1. सायर पुत्र स्व० करीमा, जाति मेहरात, निवासी ग्राम रतनपुरा सरदारा, फतेहपुरिया दोगम, तह० ब्यावर, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. दाऊ पुत्र स्व० करीमा, जाति मेहरात, निवासी ग्राम रतनपुरा सरदारा, फतेहपुरिया दोगम, तह० ब्यावर, जिला अजमेर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये जरिये लेण्ड होल्डर, तहसीलदार, ब्यावर, जिला अजमेर ।

रेस्पोंडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध विरुद्ध निर्णय व अंतिम डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर, दिनांक 6.6.2017 अंतर्गत वाद संख्या 66 / 2013.

उपस्थित:—

1. श्री शिवप्रकाश चौधरी, वकील अपीलांट ।
2. श्री महेन्द्रसिंह, वकील रेस्पोंड संख्या 1.
3. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता ।

निर्णय

दिनांक:—22.4.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 6.6.2017 के विरुद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोंड संख्या 1 दाऊ ने अधी०न्याया० में एक वाद अंतर्गत धारा 53 व 188 राज०काश्त०अधि० 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा खसरा नंबर 813, 822, 833 / 1230, 845 / 1, 846, 847 व 848 कुल कित्ता 7 कुल रकबा 6 बीघा 10 बिस्वांसी ग्राम रतनपुरा सरदारा पटवार क्षेत्र फतेहपुरिया दोगम, तहसील ब्यावर में स्थित है । उक्त आराजियात वादी व प्रतिवादी की पुश्तैनी आराजियात है जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 1 संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है । अतः वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जाकर बंटवारा करवाया जावे । वाद का नोटिस प्रतिवादी / अपीलांट को तामील

होने पर प्रतिवादी/अपीलांत ने दावे के तथ्यों से इंकार किया तत्पश्चात् परीक्षण न्यायालय ने साक्ष्य लेकर विपक्षी रेस्पोंडेंस संख्या 1 का वाद डिक्री करते हुए वादी व प्रतिवादी को बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किया व दिनांक 2.4.2014 को प्राथमिक डिक्री पारित कर दी । तत्पश्चात् अधीन्यायालय ने तहसीलदार, ब्यावर को बंटवारा स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करने का आदेश दिया जिस पर तहसीलदार स्वयं ने मौके पर जाकर बंटवारा स्कीम तैयार नहीं की व पटवारी को बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया जिस पर अपीलांत ने सहायक कलक्टर, ब्यावर के निर्णय दिनांक 18.2.2015 के विरुद्ध एक निगरानी मानचित्र राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की जिस पर मानचित्र मण्डल ने उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर की बंटवारा स्कीम को तहसीलदार के जरिये तैयार करवाने का निर्देश दिया व यह भी निर्देश दिये कि स्कीम तैयार कर, बंटवारा स्कीम पर दोनों पक्षों को आपत्तियां प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करे तत्पश्चात् अंतिम डिक्री पारित करे । इसके उपरांत अधीन्यायालय ने दिनांक 6.6.2017 को अंतिम डिक्री पारित की । अधीन्यायालय के इस निर्णय व अंतिम डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांत ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंस को तलब किया गया । रेस्पोंडेंस के उपस्थित होने तथा अधीन्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
4. विद्वान वकील अपीलांत ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विद्वान अधीन्यायालय ने तहसीलदार द्वारा तैयार की गई बंटवारा स्कीम पर अपीलांत द्वारा उठाई गई आपत्तियों जो लिखित में दिनांक 8.3.2017 को प्रस्तुत की गई थी उनकी विवेचन किये बिना व अपीलांत को सुनवाई का अवसर दिये बिना अंतिम डिक्री पारित करने में भूल की है । अधीन्यायालय ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु की ओर ध्यान नहीं दिया कि तहसीलदार द्वारा पारित बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 1.2.2017 में खसरा नंबर 845/1 पर आने जाने हेतु कोई रास्ता नहीं दिया है जिससे बंटवारा स्कीम गैर कानूनी है । इसी प्रकार खसरा नंबर 847/3 में जो पानी का धोरा दर्ज किया है वह या तो भूमिगत होना चाहिये अथवा अपीलांत को भी इस धोरे के पास की आरजी वारस्ते आवागमन दी जावे ताकि अपीलांत खसरा नंबर 847 के दक्षिणी भाग में जाने वाली सड़क का उपयोग कर सके । विद्वान वकील अपीलांत ने बहस में आगे कथन किया कि बंटवारा स्कीम में अपीलांत की 1 बिढस्वा भूमि को गलत तौर पर काटा गया है जबकि अपीलांत केवल अपने खेत की सीमा तक ही भूमि कटवाने का अधिकारी है आगे जो धोरा विपक्षी के खसरा संख्या 847/2 में जाता है उस धोरे की भूमि का क्षेत्रफल अपीलांत की भूमि से कम नहीं किया जा सकता है व इसी प्रकार यदि खसरा नंबर 847 में धोरा कायम किया जाता है तो विपक्षी को 3 फीट अंदर पाईप लाईन बिछाकर कुएं से पानी लेने का अधिकार होगा क्योंकि यदि खेत के बीच में धोरा दिया जाता है तो अपीलांत के खेत खसरा नंबर 847/1 के दो टुकड़ें हो जायेंगे व ट्रैक्टर आदि ले जाने से बार-बार धोरा टूटेगा जिससे दोनों पक्षों में विवाद होने का कारण बनेगा । उपरोक्त आपत्तियों के अलावा अपीलांत को दी गई खसरा संख्या 844/1262 की भूमि में आने जाने हेतु भी रास्ते का कोई प्रावधान स्कीम में नहीं दिया गया है जिससे अपीलांत को खसरा संख्या 844/1262 का उपयोग करने में परेशानी होगी व इसी प्रकार खसरा नंबर 822/1 को भी अपीलांत के कुरे में नहीं दिया गया है जबकि एकजाई भूमि अपीलांत को मिलनी चाहिये थी । अधीन्यायालय ने मुस्तकिल बिन्दुओं से खेतों की पैमाईश कर क्षेत्रफल की गणना सही रूप से नहीं की है व न ही कोई बंटवारे के निशानात ही कायम किये हैं । बहस में आगे कथन किया कि अधीन्यायालय ने बंटवारे की अंतिम डिक्री

में लगान का भी कोई बंटवारा नहीं किया है इस कारण भी बंटवारा स्कीम व अंतिम डिक्री काबिल निरस्तनीय है । अधी०न्याया० ने राजस्व मण्डल द्वारा बनाये गये नियम 18 से 21 की पालना नहीं की है जबकि उन्हें बंटवारा प्रस्ताव में पक्षकारों के निर्माण को भी अंकित करना चाहिये था । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी०न्याया० द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 6.6.2017 को निरस्त किया जावे तथा प्रकरण को पुनः अपीलांट की आपत्तियों का निस्तारण करते हुए बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर नये सिरे से अंतिम डिक्री पारित करने हेतु अधी०न्याया० को प्रतिप्रेषित किया जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो० संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अधी०न्याया० ने तहसीलदार, ब्यावर को स्वयं बंटवार प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने के निर्देश दिये तथा बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरांत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों पर अपीलांट को सुनकर अंतिम डिक्री पारित की है । अपीलांट ने प्रकरण में देरीना करने के उद्देश्य से अपील पेश की है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।
6. हमने उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अधी०न्याया० ने वादी/रेस्पो० संख्या 1 का वाद दिनांक 2.4.2014 को निर्णित कर प्राथमिक डिक्री पारित करने के आदेश पारित किये तथा तहसीलदार, ब्यावर को बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किये जाने पर तहसीलदार ने दिनांक 1.2.2017 को बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर अधी०न्याया० के समक्ष पेश किये है। उक्त बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरांत अधी०न्याया० के समक्ष अपीलांट/प्रतिवादी ने दिनांक 8.3.2017 को बंटवारा प्रस्ताव के संबंध में आपत्तियां पेश कर कथन किया है कि तहसीलदार, ब्यावर ने बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 1.2.2017 में खसरा नंबर 846 रकबा 0-05-00 बीघा गैर मुमकिन चाह व खसरा नंबर 847 के जल प्रवाह के लिये छोड़दी गई भूमि के बाबत् स्पष्ट बंटवारा प्रस्ताव नहीं बनाया है एवं न ही खसरा नंबर 845/1 की भूमि को अवागमन हतु छोड़ा गया है जबकि अधी०न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री दिनांक 2.4.2014 में स्पष्ट रूप से आवागमन हेतु रास्ता छोड़ने बाबत् स्पष्ट आदेश पारित किये गये थे। इसी प्रकार आराजी खसरा नंबर 846 व 847 की भूमि में अंडर ग्राउण्ड पाईप लाईन बाबत् भी कोई प्रावधान बंटवारा प्रस्ताव में अंकित नहीं किये है। अपीलांट के उक्त आपत्ति प्रार्थना पत्र का रेस्पो० संख्या 1 द्वारा दिनांक 5.4.2017 को जवाब पेश किया है किन्तु अधी०न्याया० ने बंटवारा प्रस्ताव के अनुसार दिनांक 6.6.2017 को अंतिम डिक्री पारित करते समय अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र का निस्तारण किये बिना अंतिम डिक्री पारित की है जिसे विधिसम्मत नहीं माना जा सकता है । अधी०न्याया० के समक्ष जब बंटवारा प्रस्ताव बाबत् आपत्ति एवं जवाब प्रार्थना पत्र पेश हो चुके थे तो अधी०न्याया० को उक्त आपत्तियों बाबत् पक्षकारान को सुनकर आपत्तियों का निस्तारण करने के उपरांत ही राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के अनुसार बंटवारा की अंतिम डिक्री पारित करनी चाहिये थी किन्तु अधी०न्याया० ने ऐसा न कर विधिक त्रुटि कारित की है । अधी०न्याया० द्वारा पारित अंतिम डिक्री दिनांक 6.6.2017 को विधिसम्मत नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी०न्याया० द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 6.6.2017 निरस्त योग्य एवं प्रकरण अधी०न्याया० को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।
7. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 6.6.2017 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी०न्याया० को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट/प्रतिवादी

संख्या 1 द्वारा बंटवारा प्रस्ताव के संबंध में प्रेषित प्राथमिक आपत्तियों पर उभयपक्ष को सुनकर, आपत्तियों का निस्तारण करने के उपरांत राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए पक्षकारान के मध्य विवादित भूमियों के संबंध में बंटवारा की अंतिम डिक्री पारित करे । पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)

राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 22.4.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)

राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर